Drug Licensing Policy

2788. SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether apart from the drug pricing policy Government have since evolved a separate policy covering drug licensing aspect; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Subsequent to discussions held in both the Houses of Parliament, Government announced "Modifications in the Drug Policy, 1986" on 15.9.1994, which *inter-alia* include decisions of the Government in regard to both industrial licensing aspects as well as pricing aspects of Pharmaceutical Indusry. Copies of the document containing the Modifications are available in the Parliament Library.

भू-राजस्व वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना

2789. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक उत्तर प्रदेश के सभी भू-राजस्व वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री) (डा० कृपासिंधु भोई): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल में गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

2790. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल में गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए वर्तमान कार्य योजना की अवधि किस तिथि को समाप्त हो रही है;

(ख) इस कार्य योजना की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अपूर्ण रह गए निर्माण कार्यों को किस प्रकार पूर्ण किया जाएगा; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को आगामी पांच वर्षों के लिए कोई नई कार्य योजना प्रस्तुत की है; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) से (ग) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 01.04.1990 से 31.03.1995 तक के पांच वर्षों की अवधि के लिए कुल 163 करोड़ रुपए की

लागत से एक कार्य योजना तैयार की गई थी। चूंकि इस कार्य योजना के अन्तर्गत सभी योजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं इसलिए इन सभी अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना की अवधि एक साल और (अर्थात् 31.03.96 तक) बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1996-97 से 2000-2001 की अवधि के लिए नई कार्य योजना का एक प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान विस्तरित कार्य योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

Prohibition on import of mangoes by USA

2791. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the United States of America has prohibited the import of fresh mangoes from India on grounds of pest infestation;

(b) if so, the facts in this regard;

(c) whether Government have presented the correct position and submitted all pertinent data to the Animal and Plant Health Inspection Service, USDA; and

(d) if so, the details thereof and the response of USDA thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) The United States of America has currently prohibited the import of fresh mangoes from India on grounds of pest infestation.

(c) and (d) The Dte. of Plant Protection, Quarantine & Storage, Ministry of Agriculture has requested the Animal and Plant Health Insepection Service, USDA to intimate the conditions stipulated by them/all relevant information for taking further necessary action in the matter. No response has, however, been received from USDA so far.

Institutes dealing with fisheries under ICAR

2792. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the various institutes dealing with fisheries under ICAR;

(b) the institutes which have any activity in Andhra Pradesh;

(c) whether Government will increase such activities in Andhra Pradesh; and

(d) the steps proposed to increase activities of ICAR in the fisheries sector in Andhra Pradesh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN):

(a) 1. Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), Cochin kerala.

2. Central Inland Capture Fisheries Research Institute (CICFRI), Barrackpore, West bengal.

3. Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Cochin, Kerala.

4. Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Bombay, Maharashtra.

5. Central Institute of Freshwater Aquaculture (CIFA), Kausalyagang, *via* Bhubaneswar, Orissa.

6. Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Madras, Tamil Nadu.

7. National Bureau of Fish Genetic Resources (NBGR), Lucknow, Uttar Pradesh.

8. National Research Centre on Coldwater Fishers (NRCCWF), Haldwani, Uttar Pradesh.

(b) 1. Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI).

2. Central Inland Capture Fisheries Research Institute (CICIFRI).

3. Central Institute of Fisheries